



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

No. 125]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2012/ज्येष्ठ 1, 1934

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2012/JYAISTHA 1, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2012

विषय : सऊदी अरबिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेन्टाइरायथ्रिटाल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 14/11/2011-डीजीएडी.—यतः, 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार सऊदी अरबिया (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेन्टाइरायथ्रिटाल (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए मै0 कानोरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।

## विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पेन्टाइरायथ्रिटाल है (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है)। ऐसा दावा किया जाता है कि पेन्टाइरायथ्रिटाल एक कार्बनिक यौगिक है। ऐसा दावा किया जाता है कि 'इरायथ्रिटाल' नाम 'पेन्टाइरायथ्रिटाल' से लिया गया है जिससे चार हाइड्राक्सिल ग्रुप की उपस्थिति का संकेत मिलता है और उपसर्ग 'पेन्टा' से संकेत मिलता है कि इसके मालिक्यूल में पाँच कार्बन एटम हैं।

3. आवेदक द्वारा किए उल्लेख के अनुसार 'पेण्टाइरायथ्रिटाल' या तो तकनीकी ग्रेड का या नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है। यह दावा किया जाता है कि दोनों ग्रेडों में मुख्य अन्तर इसकी शुद्धता, क्रिस्टल आकार और क्रिस्टल की एकरूपता में होता है। ऐसा दावा किया जाता है कि दोनों ग्रेडों का उत्पादन समान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। उल्लेख किया गया है कि यह ग्रेडेशन केवल उत्पादन के पश्चात और उत्पाद के विश्लेषणात्मक परीक्षण स्तर पर ही दिखाई देता है। 98% से अधिक की शुद्धता और बेहतर क्रिस्टल फार्मेशन वाले पेण्टाइरायथ्रिटाल का प्रयोग विस्फोटक उद्योग में किया जाता है और इसलिए वाणिज्यिक शब्दावली में इसको 'नाइट्रेशन ग्रेड' नाम दिया गया है। तथापि 'नाइट्रेशन ग्रेड' के रूप में ज्ञात पेण्टाइरायथ्रिटाल का प्रयोग अल्काइड रेजिन्स तथा अन्य उत्पादों (जहां अन्य ग्रेड 'टेक्निकल ग्रेड' पेण्टाइरायथ्रिटाल का प्रयोग किया जाता है) का उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है।

4. इस उत्पाद का प्रयोग अधिकांशता अल्काइड रेजिन्स, रेजिन ईस्टर्स, प्लास्टीसाइजर्स, मुद्रण स्याही, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक्स के लिए स्टैबिलाइजर्स, आशोधित ड्राइंग आयल्स, डिटोनेटर्स, विस्फोटकों, औषधों और सार तेलों तथा सिंथेटिक लुब्रीकेण्ट्स का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। यह उत्पाद सीमाशुल्क वर्गीकरण 29054200 के अन्तर्गत आता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और वे इस जाँच के दायरे के अन्तर्गत किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।

#### समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि सम्बद्ध वस्तुएं, जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समरूप हैं। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित सम्बद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यो या अन्तिम प्रयोग में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। दोनों, तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और अतः उन्हें पाटनरोधी नियमों के अन्तर्गत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाए। इस प्रकार, भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु को इस जाँच के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

#### घरेलू उद्योग की स्थिति

6. यह आवेदन मै0 कानोरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जो सम्बद्ध वस्तु का भारत में प्रमुख उत्पादक है, द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि सम्बद्ध वस्तु के इस देश में मैसर्स एशियन पेण्ट्स (इण्डिया) लिमि0 (एपीएल) और मैसर्स पर्सट्राप

केमिकल्स इण्डिया प्रा० लिमि० (पीसीआईएल) नामक दो अन्य उत्पादक हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि एपीएल सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन मुख्यतः कैप्टिव उपयोग उद्देश्य के लिये करता है, परन्तु पीसीआईएल ने जॉच अवधि के दौरान इसका उत्पादन बंद कर दिया है और वह सम्बद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात करता है। अतः प्राधिकारी यह निश्चित करते हैं कि आवेदक उद्योग नियम 2(ख) के आशय के अन्तर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुरूप स्थिति हेतु सभी मानदण्डों को पूरा करता है।

### अन्तर्गस्त देश

7. इस जॉच में शामिल देश सऊदी अरबिया है।

### सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने, सम्बद्ध वस्तु की सम्बद्ध देश में बिक्री की जाने वाली कीमत का साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण, घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत के आकलनों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। अतः प्राधिकारी ने इस जॉच की शुरुआत करने के उद्देश्य से सम्बद्ध वस्तु का सम्बद्ध देश में सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रथम दृष्ट्या विनिर्मित मूल्य के आधार पर किया है।

### निर्यात कीमत

9. आवेदक द्वारा संबद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का आकलन समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, अन्तरदेशीय भाड़ा और पत्तन व्यय के अनुरूप कीमत समायोजन करने के पश्चात् गौण स्रोतों से लेन-देनवार संग्रहित आयात आंकड़ों पर विचार करते हुए किया है।

### पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर आवेदक ने उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। यह पाया गया कि सम्बद्ध वस्तु की सम्बद्ध देश में सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से अत्यधिक ज्यादा है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देश में उत्पादित या सम्बद्ध देश से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी जॉच शुरू करना न्यायोचित है। पाटन मार्जिन का आकलन न्यूनतम से अधिक है।

### 'क्षति' और कारणात्मक सम्बन्ध

11. आवेदक ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन, कीमत में कटौती, कीमत हास और लाभदायकता, लगाई गई पूँजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह में कमी के कारण होने वाली 'क्षति' के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। सम्बद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही 'क्षति' के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे पाटनरोधी जाँच शुरू करना न्यायोचित ठहरता है।

### पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

12. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह पाते हैं कि सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षति' और पाटन तथा 'क्षति' के बीच कारणात्मक सम्बन्ध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसलिए, प्राधिकारी कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली 'क्षति' के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी डिग्री और उसके प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी उपाय की राशि, जो यदि वसूली जाती तो, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती, की सिफारिश करने के लिए जाँच शुरू करते हैं।

### जाँच अवधि

13. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक ने जाँच अवधि 1 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2011 (15 माह) का अनुरोध किया है। तथापि अद्यतन आँकड़ों के आधार पर निष्पक्ष विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी वर्तमान जाँच के उद्देश्यों के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 (12 माह) निर्धारित करते हैं। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जाँच की अवधि भी शामिल रहेगी।

### सूचना प्रस्तुत करना

14. जाँच से संबंधित सम्बद्ध देश के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात आयातकों और घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय(डीजीएडी)**  
**कमरा सं० 240, उद्योग भवन,**  
**नई दिल्ली-110011**

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जाँच से संगत जानकारी को निर्धारित समयावधि के भीतर निवेदन कर सकता है।

**15. समय सीमा**

वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु किया गया कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर पहुँच जाना चाहिए। ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों से, जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, को उन्हें पत्र भेजे जाने की तारीख से चालीस दिनों के अन्दर अपनी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह भी नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा बढ़ाने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

**16. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करेंगे और यदि किसी पक्षकार की राय में ऐसी जानकारी का सार बनाना भावप्रवण नहीं होगा तो उसके कारण का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या अन्यथा संगत अवधि के अन्तर्गत आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है या जाँच में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न करता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

182246112-2

**17. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

निर्दिष्ट प्राधिकारी, नियम 6(7) के अनुसार एक सार्वजनिक फाइल रखेंगे। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

विजय लक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2012

**Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Pentaerythritol originating in or exported from Saudi Arabia.**

**No. 14/11/2011-DGAD.**—Whereas M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of “Pentaerythritol” (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Saudi Arabia (hereinafter referred to as subject country) and requested for initiation of anti-dumping investigation for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

**PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

2. The product under consideration in the present investigation is Pentaerythritol (also referred to as subject goods hereinafter). Pentaerythritol is claimed to be an organic compound. The name “erythritol” is claimed to have been derived from “Pentaerythritol” which indicates presence of four hydroxyl groups, and the prefix “Penta” indicates that there are five carbon atoms in the molecule.

3. As stated by the applicant, Pentaerythritol can be of technical grade or nitration grade. The principal difference in the two grades is claimed to be in purity, crystal size and uniformity of crystals. Both the grades are claimed to be produced out of the same process. It has been submitted that gradation comes into picture only after production and at the stage of analytical testing of the

product. Pentaerythritol having purity above 98% and better crystal formation is stated to be used in the explosive industry and therefore, this grade has been designated as "Nitration Grade" in commercial parlance. However, Pentaerythritol considered as "Nitration Grade" can also be used for production of Alkyd Resins and other products (wherever the other grade "Technical Grade" Pentaerythritol is used).

4. The product is mostly used in the manufacture of Alkyd Resins, Resin Esters, Plasticizers, Printing inks, Synthetic rubber, Stabilizers for plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, and Core oils and Synthetic lubricants, etc. The product falls under customs classification 29054200. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the investigations.

#### Like Articles

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Anti-dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Indian industries are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country for the purpose of the present investigation.

#### DOMESTIC INDUSTRY STANDING

6. The application has been filed by M/s. Kanoria Chemicals & Industries Ltd, the major producer of the subject goods in India. The applicant has claimed that there are two more producers of the subject goods in the country namely M/s Asian Paints (India) Ltd (APL) and M/s Perstrop Chemicals India Pvt Ltd (PCIL). While APL is claimed to be primarily engaged in producing the subject goods for captive consumption purposes, PCIL is claimed to have switched over to importing subject goods in significant volumes and closed the production during POI. On the basis of information available, Authority notes that the applicant company constitutes a major proportion in Indian production. The Authority, therefore, determines that the applicant industry constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and the application

1822 a 112-3

satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the anti-dumping Rules supra.

### **COUNTRY INVOLVED**

7. The country involved in the present investigation Saudi Arabia.

### **NORMAL VALUE**

8. The applicant has constructed normal value based on estimates of cost of production of domestic industry, due to unavailability of the evidence of the price at which the material is being sold in the subject country. The Authority has therefore considered prima facie the normal value of subject goods in the subject country on the basis of constructed value for the purpose of initiation of investigation.

### **EXPORT PRICE**

9. Export price of the subject goods from the subject countries has been estimated by the applicant considering transaction-wise import data collected from Secondary Sources, after making price adjustments on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Inland Freight and Port expenses.

### **DUMPING MARGIN**

10. Based on the normal value and export price, the applicant has determined dumping margin for the product. It is found that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation. The dumping margins are estimated to be above *de minimis*.

### **INJURY AND CAUSAL LINK**

11. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price suppression and decline in profitability, return on capital employed and cash flow for the domestic industry. There is sufficient evidence of the 'injury' being suffered by the applicant



caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

### **INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS**

12. In view of the above the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist and therefore the Authority, in terms of Rule 5 of the Anti Dumping Rules hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and recommend the amount of anti dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

### **PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

13. The petitioner had proposed 1st April, 2010 to 30th June, 2011 (15 months) as the POI. However, for ensuring fair analysis on the basis of updated data, the Authority determines the Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation as 1st January, 2011 to 31st December, 2011 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2008-09, 2009-10, 2010-11 and the POI.

### **14. SUBMISSION OF INFORMATION**

The exporters in the subject country, Government through the Embassy, importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

**The Designated Authority  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Commerce  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD)  
Room No. 240, Udyog Bhavan,  
New Delhi-110011**

Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, within the time limit set out below.

**15. TIME LIMIT**

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

**16. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS**

In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

**17. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority